प्रकाशन हेतु अनुमोदन

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

माध्यस्थम अपील क्र. 33/2007

अपीलार्थी : केन्द्रीय खान योजना एवं डिजाइन संस्थान लिमिटेड

बनाम

प्रत्यर्थी : श्री सौरव अग्रवाल व एक

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

विचारार्थ प्रस्तुत निर्णय

न्यायमूर्ति

21-02-2012

माननीय डा**. आई**. **एम**. **कुद्दूसी**, **न्यायमूर्ति**

मै सहमत हूँ।

सही/-

आई. एम. कुद्दूसी

न्यायमूर्ति

23 फरवरी, 2012 को निर्णय सुनाए जाने के लिए सूचीबद्ध करे।

सही/-

प्रशांत कुमार मिश्रा

न्यायमूर्ति

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

माध्यस्थम अपील क्र. 33/2007

अपीलार्थी : केन्द्रीय खान योजना एवं डिजाइन संस्थान लिमिटेड

बनाम

प्रत्यर्थी : श्री सौरव अग्रवाल व एक

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

उपस्थित:

अपीलार्थी की ओर से : श्री जगदीप धनखड़, वरिष्ठ अधिवक्ता, श्री पी. एस. कोशी, एवं श्री विवेक वर्मा।

प्रत्यर्थी की ओर से : श्री एस. सी. पांडे, वरिष्ठ अधिवक्ता, श्री अनिल पांडे एवं श्री के. आर. नायर।

युगल पीठ : माननीय न्यायमूर्ति **डा. आई. एम. कुद्दूसी**

माननीय न्यायमूर्ति **श्री प्रशांत कुमार मिश्रा**

निर्णय

(23/02/2012 को प्रदत्त)

न्यायालय का निम्नलिखित निर्णय **न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा** द्वारा सुनाया गया।

1. माध्यस्थम एवं सुलह अधिनियम, 1996 (जिसे आगे '1996 का अधिनियम' कहा जाएगा) की धारा 37 के तहत यह अपील, अपीलार्थी/गैर दावाकर्ता द्वारा जिला न्यायाधीश, बिलासपुर द्वारा एमजेसी क्र. 39/06 में पारित आदेश को चुनौती देते हुए दायर की गई है, जिसमें उक्त अपील खारिज कर दी गई थी। यह अपील एकल मध्यस्थ द्वारा दिनांक 31-1-2006 को पारित निर्णय के विरुद्ध थी, जिसमें दावाकर्ता स्वर्गीय बी.पी. अग्रवाल के पुत्र श्री सौरव अग्रवाल के पक्ष में और अपीलार्थी के विरुद्ध ब्याज सहित 2,07,27,733.83/- रुपये की राशि प्रदान की गई थी। मध्यस्थ ने अपीलार्थी /गैर-दावाकर्ता द्वारा किए गए 34,04,863.88/- रुपये के प्रतिदावे को भी ब्याज सहित स्वीकार कर लिया था। इस प्रकार उक्त प्रतिदावे की राशि घटाने के बाद, दावाकर्ता/प्रतिवादी के पक्ष में पारित कुल राशि 1,73,22,869.95/- रुपये थी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

2. मामले का संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि 23-12-1994 को अपीलार्थी द्वारा केन्द्रीय खान योजना एवं डिजाइन संस्थान लिमिटेड, बिलासपुर (संक्षेप में सीएमपीडीआइएल) के आवासीय परिसर के निर्माण के लिए निविदा आमंत्रित करते हुए एक निविदा सूचना जारी की गई थी। निविदा प्रक्रिया के अंत में,

दावाकर्ता को सफल पाया गया और उसे 21-8-1995 के कार्य आदेश द्वारा 2,48,76,391.51 रुपये के करार मूल्य का ठेका दिया गया। निविदा दस्तावेज में उल्लेखित 20 महीनों की निर्धारित अवधि के भीतर कार्य पूरा किया जाना था। 5-1-1996 को एक करार निष्पादित किया गया और दावाकर्ता ने कार्य शुरू किया, हालांकि, दोनों पक्षों के बीच मतभेद उत्पन्न हो गए और उनके द्वारा हस्ताक्षरित करार के अनुसार कार्य पूरा नहीं हो सका। करार के खंड 14 में विवादों के निपटारे के लिए माध्यस्थम का प्रावधान था और दावाकर्ता के अनुरोध पर, 15/17-3-2004 को मध्यस्थ नियुक्त किया गया। मध्यस्थ के समक्ष, दावाकर्ता ने 31-3-2004 तक और उसके बाद वास्तविक भुगतान तक 18% की दर से ब्याज सहित 9,55,57,702.47 रुपये की राशि का दावा प्रस्तुत किया। दावे का विवरण अधिनिर्णय के पैरा 4(x) में दिया गया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

3. अपीलार्थी /गैर-दावाकर्ता ने दावे को पूरी तरह से नकार दिया और कहा कि दावा स्वीकार्य नहीं है क्योंकि वैसे भी करार में दिए गए आंतरिक विनियमों का पालन नहीं किया गया है। दावे को गुणानुगुण के आधार पर खारिज कर दिया जाना चाहिए। गैर-दावाकर्ता ने 18% ब्याज सहित 2,67,20,323.84 रुपये का प्रतिदावा प्रस्तुत किया, जिसका विवरण निर्णय के अनुच्छेद-7(vi) में दिया गया है।

4. मध्यस्थ ने इस निर्णय के अनुच्छेद-1 में उल्लेखित के अनुसार दावाकर्ता के पक्ष में अधिनिर्णय पारित किया। अपीलार्थी ने 1996 के अधिनियम की धारा 34 (2) के

तहत जिला न्यायाधीश के समक्ष अपील दायर की। माननीय जिला न्यायाधीश ने अपील अपास्त कर दी, जिसे इस न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई है।

5. अपीलार्थी की ओर से विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री जगदीप धनखड़ और अधिवक्ता श्री पी.एस. कोशी ने तर्क दिया कि करार की शर्तों और विशेष रूप से माध्यस्थम खंड के विपरीत माध्यस्थम प्रक्रिया शुरू की गई थी, इसलिए, निर्णय और अपीलीय आदेश को रद्द किया जाना चाहिए। दूसरा, उन्होंने तर्क दिया कि करार के अनुसार दावा माध्यस्थम योग्य नहीं था और इसलिए यह निर्णय करार में स्पष्ट रूप से उल्लेखित प्रावधानों का घोर उल्लंघन है। यह तर्क दिया गया है कि यह निर्णय अनुचित और अस्वीकार्य है क्योंकि नियुक्ति आदेश की गलत व्याख्या की गई है और उसमें एक ऐसी स्थिति को शामिल किया गया है जो वास्तव में मौजूद नहीं है, साथ ही वैधानिक प्रावधानों की अनदेखी की गई है। अंत में, यह ज़ोर देकर कहा गया है कि निर्णय तर्कसंगत होना चाहिए था, जबकि विभिन्न मदों के अंतर्गत राशि तय करते समय नाम के संबंध में कोई कारण नहीं बताया गया है और इस कारण से भी, यह निर्णय रद्द किए जाने योग्य है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

6. इसके विपरीत, प्रतिवादी की ओर से विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री एस.सी. पांडे और अधिवक्ता श्री के.आर. नायर ने तर्क दिया कि निर्णय तर्कसंगत है क्योंकि विभिन्न अनुच्छेदों में कारण बताए गए हैं, इसलिए इसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि मध्यस्थ ने अपीलार्थी द्वारा उठाए गए

प्रतिदावे के एक हिस्से को भी स्वीकार कर लिया है और उसे स्वीकार कर लिया है, जिसे इस अपील में चुनौती नहीं दी गई है, और चूंकि निर्णय के एक हिस्से को चुनौती नहीं दी जा सकती है, इसलिए वर्तमान अपील विचारणीय नहीं है, क्योंकि अपीलार्थी को एक ही समय में दोहरी बात करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। यह भी तर्क दिया गया है कि दावा माध्यस्थम योग्य था और पक्षों के बीच 4-2-2000 को हुए करार के बावजूद, माध्यस्थम करार के तहत दावाकर्ता का अधिकार समाप्त नहीं होता है।

7. यह न्यायालय अपीलार्थी द्वारा उठाए गए आपत्ति के आधारों पर एक-एक करके विचार करेगा। यद्यपि, माध्यस्थम खंड के प्रावधानों के विरुद्ध माध्यस्थम तंत्र को क्रियान्वित किए जाने से संबंधित आपत्ति का आधार, यदि पहले विचार के लिए लिया जाए, तो विधिक प्रक्रिया के साथ-साथ माध्यस्थम और उसके परिणामस्वरूप दिया गया निर्णय और अपीलीय आदेश विधिक रूप से गलत है। इस संबंध में, माध्यस्थम खंड का उल्लेख करना आवश्यक है, जिसे त्वरित संदर्भ के लिए नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया है:-

> 14.1. ठेकेदार का यह दायित्व है कि वह कार्य निष्पादन के दौरान मुकदमेबाज़ी और विवादों से बचे। हालांकि, यदि ठेकेदार और विभाग के बीच ऐसे विवाद उत्पन्न होते हैं, तो कंपनी द्वारा इस उद्देश्य के लिए गठित विभिन्न स्तरों की समितियों के माध्यम से विवादों को निपटाने का

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

प्रयास किया जाएगा। ठेकेदार को ऐसे विवादों/दावों के निपटारे के लिए प्रभारी अभियंता को लिखित में अनुरोध करना चाहिए; अन्यथा कंपनी ठेकेदार के किसी भी विवाद/दावे पर विचार नहीं करेगी। यदि मतभेद फिर भी बने रहते हैं, तो ठेकेदार प्रभारी अभियंता को मामले को एकल मध्यस्थ के पास भेजने के लिए लिखित में अनुरोध कर सकता है। ठेकेदार को उपरोक्त समिति के विवादों/दावों के संबंध में प्रभारी अभियंता से अंतिम निर्णय की सूचना प्राप्त होने के 90 (नब्बे) दिनों के भीतर ऐसा अनुरोध करना होगा; अन्यथा ठेकेदार के दावे, मतभेद या विवाद को माफ किया हुआ माना जाएगा और कंपनी इन दावों के संबंध में करार के तहत सभी दायित्वों से मुक्त हो जाएगी। हालांकि, ठेकेदार के अनुरोध को स्वीकार करना कंपनी का विशेषाधिकार है। एकमात्र मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

14.2. जब तक करार में अन्यथा प्रावधान न हो, विनिर्देशों, डिज़ाइनों, रेखाचित्रों और निर्देशों के अर्थ से संबंधित सभी प्रश्न और विवाद, तथा कार्य में प्रयुक्त कारीगरी या सामग्री की गुणवत्ता से संबंधित, या करार, डिज़ाइन, रेखाचित्र, विनिर्देशों, अनुमानों, निर्देशों, आदेशों या शर्तों से किसी भी तरह से उत्पन्न होने वाले या उनसे संबंधित किसी अन्य प्रश्न, दावे, अधिकार, मामले या वस्तु से संबंधित, चाहे वह कार्य की प्रगति के

प्रारंभ के दौरान उत्पन्न हो या उसके पूरा होने या परित्याग के बाद, कंपनी द्वारा विवादों के निपटारे में विफल रहने पर और ठेकेदार के अनुरोध पर, खंड 14.1 के अनुसार, कंपनी के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक द्वारा नियुक्त एकमात्र मध्यस्थ को संदर्भित किए जाएंगे।कंपनी या उसके द्वारा अधिकृत कोई अन्य व्यक्ति, ऐसे मध्यस्थ की नियुक्ति कर सकता है।

इस प्रकार की किसी भी नियुक्ति पर कोई आपत्ति नहीं होगी यदि नियुक्त मध्यस्थ कंपनी का कर्मचारी है और कंपनी के कर्मचारी के रूप में अपने कर्तव्यों के निर्वाह में उसने विवाद या मतभेद के सभी या किसी भी मामले पर अपने विचार व्यक्त किए हैं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

यदि मध्यस्थ, जिसे मूल रूप से मामला सौंपा गया है, का तबादला हो जाता है, वह अपना पद छोड़ देता है, या किसी भी कारण से कार्य करने में असमर्थ हो जाता है, तो कंपनी के मुख्य मध्यस्थ (सीएमडी) या उनके द्वारा उपर्युक्त मध्यस्थ नियुक्त करने के लिए अधिकृत कोई भी व्यक्ति, तबादले, पद छोड़ने या कार्य करने में असमर्थ होने की स्थिति में, करार की शर्तों के अनुसार, उनके स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति को मध्यस्थ के रूप में नियुक्त करेगा। ऐसा व्यक्ति उस चरण से मामले को आगे बढ़ाने का हकदार होगा जहां से उसके पूर्ववर्ती ने इसे छोड़ा था। इस करार की यह भी शर्त है कि उपर्युक्त रूप से कंपनी के सीएमडी द्वारा

नियुक्त व्यक्ति के अलावा कोई अन्य व्यक्ति मध्यस्थ के रूप में कार्य नहीं करेगा, और यदि किसी कारणवश यह संभव नहीं है, तो मामले को माध्यस्थम के लिए भेजा ही नहीं जाएगा। उन सभी मामलों में जहां विवादित दावे की राशि 75,000/- रुपये (पचहत्तर हजार रुपये) या उससे अधिक है, मध्यस्थ को निर्णय के लिए कारण बताना होगा। उपरोक्त के अधीन रहते हुए, माध्यस्थम अधिनियम, 1940 या इसके किसी भी वैधानिक संशोधन या पुनर्अधिनियमन तथा इसके अंतर्गत बनाए गए तथा उस समय लागू नियमों के प्रावधान इस खंड के अंतर्गत माध्यस्थम कार्यवाही पर लागू होंगे।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

करार की यह शर्त है कि माध्यस्थम का सहारा लेने वाला पक्ष इस खंड के तहत माध्यस्थम के लिए संदर्भित किए जाने वाले विवाद या विवादों को बिंदुवार विवरण और प्रत्येक विवाद के संबंध में दावा की गई राशि या राशियों के साथ लिखित रूप में निर्दिष्ट करेगा।

माध्यस्थम कार्यवाही के दौरान ठेकेदार द्वारा करार के तहत काम जारी रखा जाएगा, जब तक कि कंपनी द्वारा लिखित रूप में अन्यथा निर्देश न दिया जाए या जब तक मामला ऐसा न हो कि मध्यस्थ का निर्णय आने तक कार्य जारी नहीं रखा जा सकता। कंपनी द्वारा देय भुगतान को माध्यस्थम कार्यवाही के कारण रोका नहीं जा सकता, जब तक कि वह माध्यस्थम कार्यवाही का विषय न हो। मध्यस्थ

द्वारा दोनों पक्षों को पहली सुनवाई की तिथि निर्धारित करने वाला नोटिस जारी करने की तिथि से माध्यस्थम कार्यवाही में प्रवेश करना आवश्यक माना जाएगा। ठेकेदार का अंतिम बिल करार के अनुसार प्रभारी अभियंता की संतुष्टि के अनुरूप पूर्ण किए गए सभी कार्यों के लिए भुगतान किया जाएगा, सिवाय उन कार्यों के जिनके लिए करार की शर्तों के अनुसार मामला एकल मध्यस्थ को भेजा गया है।

करार।

मध्यस्थ को ऐसे विवाद या मतभेद/दावे के संबंध में अलग से निर्णय देना होगा। माध्यस्थम का स्थान या तो कंपनी का मुख्यालय होगा या वह स्थान होगा जहां विवाद उत्पन्न हुआ हो, जैसा कि मध्यस्थ अपने विवेक से तय करेगा।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

8. अपीलार्थी के अनुसार, दावाकर्ता द्वारा करार के खंड-14 में दिए गए तंत्र का पालन न करने के कारण, संपूर्ण माध्यस्थम कार्यवाही शून्य है, जबकि प्रतिवादी के अनुसार, अपीलार्थी मध्यस्थ की अधिकारिता को चुनौती नहीं दे सकता, क्योंकि नियुक्ति कंपनी के सीएमडी द्वारा ही की गई है और करार के खंड-14.1 की अंतिम दो पंक्तियों के अनुसार, ठेकेदार के एकमात्र मध्यस्थ की नियुक्ति के अनुरोध को स्वीकार करना कंपनी का विशेषाधिकार है, जो एक अनन्य और विशेष अधिकार है, जिसका प्रयोग किए जाने के बाद, यह भी कहा गया है कि अपीलार्थी इसे बाद में चुनौती नहीं दे सकता। अपीलार्थी अपने ही सीएमडी के

कार्य पर प्रश्न नहीं उठा सकता क्योंकि वह अपनी ही गलती का लाभ नहीं उठा सकता और वास्तव में दावाकर्ता ने ही प्रारंभ में प्रभारी अभियंता के समक्ष विवाद में ।

9. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने **जबलपुर नगर निगम और अन्य बनाम राजेश कंस्ट्रक्शन कंपनी**[1] और **इंडिया हाउसहोल्ड एंड हेल्थकेयर लिमिटेड बनाम एलजी हाउसहोल्ड एंड हेल्थकेयर लिमिटेड**[2] के मामलों में दिए गए निर्णयों पर भरोसा किया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

10. वर्तमान मामले में, करार के खंड 14.1 में यह प्रावधान है कि यदि ठेकेदार और विभाग के बीच विवाद उत्पन्न होते हैं, तो सर्वप्रथम कंपनी की विभिन्न स्तर की समितियों के माध्यम से विवादों के निपटारे का प्रयास किया जाएगा और ठेकेदार को ऐसे विवादों/दावों के निपटारे के लिए प्रभारी अभियंता को लिखित में अनुरोध करना होगा, अन्यथा कंपनी द्वारा ठेकेदार के किसी भी विवाद/दावे पर विचार नहीं किया जाएगा। यदि मतभेद फिर भी बने रहते हैं, तो ठेकेदार प्रभारी अभियंता को मामले, को एकमात्र मध्यस्थ के पास भेजने के लिए लिखित में अनुरोध कर सकता है और यह अनुरोध ठेकेदार द्वारा उपरोक्त समिति के विवादों/दावों के संबंध में प्रभारी अभियंता से अंतिम निर्णय की सूचना प्राप्त होने के 90 दिनों के भीतर किया जाना चाहिए, अन्यथा ठेकेदार के दावों/मतभेदों या

---

[1] (2007) 5 एससीसी 344

[2] (2007) 5 एससीसी 510

विवादों को माफ किया हुआ माना जाएगा और कंपनी इन दावों के संबंध में करार के तहत सभी दायित्वों से मुक्त हो जाएगी। अभिलेख से यह प्रतीत होता है कि दावाकर्ता ने 17-11-1999 और 29-11-1999 के पत्रों में विवाद को माध्यस्थम के लिए भेजने का अनुरोध किया था और उसके बाद 4-2-2000 को सौहार्दपूर्ण निपटारे के लिए दोनों पक्षों के बीच एक बैठक हुई और वास्तव में उसी दिन समझौता हो गया, जिसे अपीलार्थी के सक्षम प्राधिकारी ने 11-2-2000 को विधिवत अनुमोदित कर दिया था। हालांकि, ऐसा प्रतीत होता है कि विवाद जारी रहे, जिसके लिए दोनों पक्षों ने एक-दूसरे पर दोषारोपण किया और अंततः 12-4-2003 को समझौता समाप्त कर दिया गया। यदि दावाकर्ता के अनुसार विवाद अभी भी जारी थे, तो उसे 90 दिनों के भीतर प्रभारी अभियंता से मामले को एकमात्र मध्यस्थ के पास भेजने का अनुरोध करना चाहिए था।हालांकि, कई दिनों तक दावाकर्ता ने न तो प्रभारी अभियंता को विवाद उठाते हुए पत्र लिखा और न ही मामले को एकमात्र मध्यस्थ के पास भेजने का अनुरोध किया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

11. **जबलपुर नगर निगम और अन्य** (पूर्वोक्त) के मामले में, अनुच्छेद-16 में यह माना गया है कि ऐसी स्थिति में जहां माध्यस्थम समझौता, मध्यस्थ की नियुक्ति सुनिश्चित करने के लिए अन्य उपायों का प्रावधान करता है, तो उनका पालन किया जाएगा और जब ऐसे आंतरिक तंत्र का पालन नहीं किया जाता है, तो मध्यस्थ को करार की शर्तों के बाहर नियुक्त नहीं किया जा सकता है।

12. इसी प्रकार, **इंडिया हाउसहोल्ड एंड हेल्थकेयर लिमिटेड** (पूर्वोक्त) के मामले में अनुच्छेद 24 और 27 में यह माना गया है कि मध्यस्थ की नियुक्ति तब तक वैधानिक और मान्य नहीं है जब तक कि पक्षों के बीच सहमत प्रक्रिया और तंत्र का पालन न किया जाए। उक्त मामले में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **नेशनल हाइवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया बनाम भूमिहाइवे डीडीबी लिमिटेड** {(2006) 10 एससीसी 763} के मामले में अपने पूर्व के निर्णय का अनुसरण किया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

13. दावाकर्ता/प्रतिवादी ने यह तर्क दिया है कि अपीलार्थी ने माध्यस्थम कार्यवाही में भाग लिया है और प्रतिदावा भी उठाया है, इसलिए वह मध्यस्थ न्यायाधिकरण के अधिकार क्षेत्र को चुनौती देने का हकदार नहीं है, बल्कि उसे ऐसा करने से रोका गया है। मध्यस्थ ने अपने निर्णय के अनुच्छेद-16 में अपीलार्थी द्वारा उठाई गई इस प्रारंभिक आपत्ति पर भी विचार किया है और यह माना है कि चूंकि मध्यस्थ की नियुक्ति सहमति से हुई थी, जैसा कि नियुक्ति में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि दोनों पक्ष माध्यस्थम के माध्यम से विवाद को निपटाने के लिए सहमत हुए थे, इसलिए मामला माध्यस्थम के लिए भेजा गया था, ऐसी प्रारंभिक आपत्ति असंगत है और अपास्त किए जाने योग्य है।

मध्यस्थ की नियुक्ति के संबंध में दिनांक 15/17 मार्च, 2004 के आदेश का संदर्भ लेना आवश्यक है ताकि यह समझा जा सके कि क्या अपीलार्थी ने नियुक्ति

के लिए सहमति दी थी और यदि हां, तो उक्त सहमति का वैधानिक प्रभाव क्या है। आदेश का सुसंगत भाग नीचे दिया गया है:-

<u>संदर्भ की शर्तें</u>

"करार से उत्पन्न होने वाले सभी मामलों का निपटारा, जो माध्यस्थम करार, अर्थात् करार के खंड 14 के अनुसार, करार दस्तावेज़ की शर्तों और माध्यस्थम एवं सुलह अधिनियम, 1996 के अनुसार किया जा सकता है। पक्षकार अपनी इच्छानुसार किसी भी वैधानिक प्रश्न को उठाने के लिए स्वतंत्र होंगे, जिसमें मध्यस्थ अधिकरण की अधिकारिता, सीमाएँ और अन्य विधिक प्रश्न शामिल हैं। मध्यस्थ सभी प्रश्नों और विवादों का निराकरण विधि के अनुसार करेगा और यदि CM-PDIL, RI-V द्वारा प्रतिदावा उठाया जाता है तो उस पर भी निर्णय देगा।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

यह पत्र दिनांक 03.10.03 को आपके द्वारा एकमात्र मध्यस्थ के रूप में कार्यभार ग्रहण करने की सहमति और मेरे दिनांक 15.3.2004 के पत्र के अनुसार भुगतान की शर्तों और नियमों पर आपकी सहमति के संदर्भ में है। शुल्क और व्यय दोनों पक्षों द्वारा समान रूप से साझा किए जाएंगे।

आपसे अनुरोध है कि आप मामले की सुनवाई शुरू होने की तारीख से जल्द से जल्द अपना युक्तियुक्त अधिनिर्णय प्रस्तुत करें।

14. संदर्भ की शर्तों को पढ़ने से इस न्यायालय को यह प्रतीत नहीं होता कि अपीलार्थी ने मध्यस्थ की नियुक्ति पर सहमति दी थी। वास्तव में, मध्यस्थ की

नियुक्ति के आदेश में ही यह उल्लेख किया गया है कि पक्षकार अपनी इच्छानुसार किसी भी विधि संबंधी प्रश्न को उठाने के लिए स्वतंत्र होंगे, जिसमें मध्यस्थ अधिकरण की अधिकारिता, समयसीमा और अन्य विधि संबंधी प्रश्न शामिल हैं। अतः, 1996 के अधिनियम की धारा 16 (2) के आधार पर यह नहीं कहा जा सकता कि अपीलार्थी मध्यस्थ न्यायाधिकरण के क्षेत्राधिकार को चुनौती देने से वंचित था। यह आपत्ति मध्यस्थ के समक्ष ही उठाई गई थी, इसलिए यह भी नहीं कहा जा सकता कि इसे पहली बार इस न्यायालय के समक्ष उठाया गया है।

15. इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि मध्यस्थ की नियुक्ति के संबंध में करार के खंड 14 में दिए गए आंतरिक तंत्र का दावाकर्ता द्वारा पालन नहीं किया गया है, इस न्यायालय का यह मत है कि **जबलपुर कॉर्पोरेशन और अन्य** एवं **इंडिया हाउसहोल्ड एंड हेल्थकेयर लिमिटेड** (पूर्वोक्त) मामलों में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित विधि के मद्देनजर के मामले में, मध्यस्थ न्यायाधिकरण को माध्यस्थम कार्यवाही करने की कोई अधिकारिता नहीं थी क्योंकि नियुक्ति स्वयं करार की शर्तों के विपरीत थी। अतः, जिला न्यायाधीश द्वारा पारित आक्षेपित आदेश और परिणामस्वरूप दिनांक 31-1-2006 का निर्णय इसी आधार पर अपास्त किए जाने योग्य है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

16. अपीलीय आदेश और परिणामस्वरूप दिए गए अधिनिर्णय की वैधता और औचित्यता को चुनौती देने का अगला आधार यह है कि निर्णय तर्कसंगत नहीं है

और इसलिए इसे रद्द किया जाना चाहिए। इस तर्क के समर्थन में अपीलार्थी ने यह तर्क दिया है कि नियुक्ति आदेश के तहत ही मध्यस्थ को युक्तियुक्त अधिनिर्णय देने के लिए कहा गया था और वैसे भी 1996 के अधिनियम की धारा 31 (3) के तहत, जब तक कि पक्षकारों ने यह सहमति न दी हो कि कोई कारण नहीं दिया जाना है, माध्यस्थम निर्णय में उन कारणों का उल्लेख होना चाहिए जिनके आधार पर इसे पारित किया गया है।

17. पूर्वोक्त तर्क को विस्तार से समझाते हुए, अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने न्यायालय का ध्यान निर्णय के सुसंगत भाग (ग) क्रियात्मक भाग की ओर दिलाया, जो पेपर बुक के पृष्ठ 58 से आगे है। दूसरी ओर, प्रतिवादी की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने पुरजोर तर्क दिया कि मध्यस्थ ने कारण तो बताए हैं, लेकिन वे सामान्यतः प्रशिक्षित न्यायाधीश द्वारा बताए जाने वाले कारणों के समान नहीं हैं। उनके अनुसार, निर्णय 70 पृष्ठों का है और निर्णय का कम से कम एक भाग अपीलार्थी द्वारा स्वीकार किए गए दावे पर आधारित है, इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि निर्णय तर्करहित है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

18. पृष्ठ 58 पर दावा किए गए दावों के संबंध में निर्णय देते समय, मध्यस्थ ने उल्लेख किया है कि दावाकर्ता ने वित्तीय दावे को 9 शीर्षों में विभाजित किया है, जिसमें पहले शीर्ष में 6 उपशीर्ष और इसके दूसरे उपशीर्ष में 20 बिंदु हैं, और आगे यह घोषणा की है कि "मैंने निर्णय देते या असहमत होते समय तर्क देने का

प्रयास किया है, जिसका विवरण नीचे दिया गया है:" इसका अर्थ यह है कि निर्णय के पूर्व भाग में केवल दोनों पक्षों का पक्ष और अपीलार्थी द्वारा उठाई गई प्रारंभिक आपत्तियों का उल्लेख है, और वास्तविक निर्णय के लिए तर्क पर निर्णय इसी अनुच्छेद से शुरू होता है। हालांकि, पृष्ठ 59 पर खंड 1 (क) में, बिना माप के किए गए कार्य के मूल्य के दावे पर विचार करते हुए, यह कहा गया है कि इस प्रकार के निर्माण कार्यों में, कुछ मदें बिना मापे रह सकती हैं, विशेष रूप से जब माप एकतरफा किए जाते हैं, और उसके बाद यह कहा गया है कि पक्षों द्वारा लिए गए रुख को ध्यान में रखते हुए और प्रतिवादी/प्रबंधन द्वारा किए गए अंतिम माप एकतरफा होने के कारण, वह 9,79,630.54 रुपये का 25% देने के लिए इच्छुक हैं। यह पूरी तरह से निराधार अनुमान प्रतीत होता है, जिसका मध्यस्थ द्वारा कोई तर्क नहीं दिया गया है। इसी प्रकार अनुच्छेद 1(ख) में, जिसका अंतिम भाग पृष्ठ 62 पर है, यह देखा गया है कि 'इन बिंदुओं पर दावाकर्ता के दावों और प्रतिवादियों के उत्तर की जांच करने के बाद, यह पाया गया है कि कुछ मामलों में पूरा दावा उचित है जबकि कुछ अन्य में यह आंशिक रूप से उचित है। ऐसे कुछ ही मामले हैं जहां दावा स्वीकार नहीं किया जा सकता है।' इसमें आगे कहा गया है कि इन सभी बातों पर विचार किए बिना, अधिकरण का मानना है कि इस उपशीर्षक 1 (ख) के अंतर्गत दावे का 50% हिस्सा स्वीकार किया जा सकता है, और इसलिए इस उपशीर्षक के अंतर्गत 23,69,942.50 रुपये का अधिनिर्णय

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

दिया जाता है। यदि मध्यस्थ की राय थी कि कुछ दावे उचित हैं, कुछ आंशिक रूप से उचित हैं और अन्य स्वीकार नहीं किए जा सकते, तो उन्हें अनुमान लगाने और बिना कोई कारण बताए दावे का 50% हिस्सा स्वीकार करने के बजाय दावों को अलग-अलग करने का प्रयास करना चाहिए था। फिर भी, उपशीर्षक 1 (ग), 1 (च), 4, 5, 6 के अंतर्गत अधिनिर्णय देते समय, दावे का अधिनिर्णय अनुमान के आधार पर दिया गया है और इस प्रकार वे स्पष्ट रूप से बिना किसी कारण के प्रतीत होते हैं।

19. **री पॉयसर और मिल्स के माध्यस्थम** मामले में {(1963) 1 ऑल ईआर 612 (क्यूबीडी)}, इस प्रकार कहा गया है:-

> यह कहना बहुत कठिन है कि क्या इसे निर्णय के आधार पर उचित रूप से गलत माना जाना चाहिए। मैं यह कहने के लिए बाध्य हूँ, और मुझे नहीं लगता कि जमींदार के अधिवक्ता ने इस बात का पूरी तरह से खंडन किया है, कि इतना तुच्छ कारण संतोषजनक नहीं है, लेकिन मेरी राय में यह इससे कहीं आगे जाता है। न्यायाधिकरण और जांच अधिनियम, 1958 की धारा 12 का पूरा उद्देश्य उन व्यक्तियों को सक्षम बनाना था जिनकी संपत्ति या हित किसी प्रशासनिक निर्णय या किसी वैधानिक माध्यस्थम से प्रभावित हो रहे थे, ताकि यदि निर्णय उनके विरुद्ध हो, तो उन्हें यह पता चल सके कि इसके कारण क्या थे। तब

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

तक, किसी अधिकारी के निर्णय से किसी व्यक्ति की संपत्ति और अन्य हित गंभीर रूप से प्रभावित हो सकते थे, निर्णय पूरी तरह से सही हो सकता था, लेकिन जिसके विरुद्ध निर्णय लिया गया था, उसे इस बात की वास्तविक शिकायत रहती थी कि उसे यह नहीं बताया गया कि निर्णय क्यों लिया गया था। धारा 12 का उद्देश्य इसका निवारण करना था, और कृषि जोत अधिनियम, 1948 के तहत माध्यस्थम के संबंध में इसका निवारण करना था। अब, संसद यह प्रावधान होने के बावजूद कि कारण बताए जाने चाहिए, मेरे विचार से इसका स्पष्ट अर्थ यह है कि उचित और पर्याप्त कारण बताए जाने चाहिए; जो कारण बताए गए हैं, चाहे वे सही हों या गलत, वे न केवल समझने योग्य होने चाहिए, बल्कि यह भी कहा जा सकता है कि वे उठाए गए महत्वपूर्ण बिंदुओं से उचित रूप से निपटते हैं, और मेरे विचार से इस वैधानिक प्रावधान को माध्यस्थम निर्णय के स्वरूप से संबंधित प्रावधान मानना उचित है। यदि कारण बताए जाने से पहले निर्णय का प्रारंभिक स्वरूप किसी भी तरह से स्वरूप संबंधी वैधानिक प्रावधानों का पालन करने में विफल रहा होता, तो यह कहने का आधार होता कि निर्णय प्रथम दृष्टया गलत था, और अब जबकि संसद ने कारणों को शामिल करने की आवश्यकता जताई है, मेरा मानना है कि यदि वे कारण संसद द्वारा निर्धारित स्वरूप का

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

उचित रूप से पालन नहीं करते हैं, तो यह निर्णय में प्रथम दृष्ट्या त्रुटि है, और यदि कारण एक अलग पत्र में दिए गए हैं तो भी यही बात लागू होती है। मेरे विचार से, 30 जुलाई, 1962 (4) के पत्र के अनुच्छेद (iii) को ध्यान में रखते हुए, इस निर्णय सहित उक्त कारणों से, 1958 के अधिनियम की धारा 12 के अनुसार, उचित प्रारूप का अनुपालन नहीं होता है और इसलिए इसमें त्रुटि है। निर्णय के संदर्भ में: मेरे विचार से, यह निर्णय में स्पष्ट रूप से विधि की त्रुटि है, जिसे उचित रूप से इसी प्रकार वर्णित किया जा सकता है, न कि तकनीकी कदाचार। यहाँ कोई भी मध्यस्थ की ओर से वास्तविक कदाचार का सुझाव नहीं देता है, लेकिन यह संभव है कि यहाँ जो कुछ गलत हुआ है, उसे निर्णय में स्पष्ट रूप से कदाचार और विधि की त्रुटि दोनों के रूप में वर्णित किया जा सकता है। यदि ऐसा है, तो मेरे विचार से, यह तथ्य कि यह बाद वाला है, इसे इस न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में लाता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

मैं यह बिल्कुल नहीं चाहता कि एक पल के लिए भी यह समझा जाए कि मैं यह कह रहा हूँ कि सुनवाई में उठाए गए प्रत्येक बिंदु के संबंध में कोई भी छोटी या मामूली त्रुटि, या कारण न बता पाना, इस न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को लागू करने के लिए पर्याप्त होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को लागू करने के

लिए दिए गए कारणों में कुछ न कुछ गड़बड़ी और अपर्याप्तता होनी चाहिए। वर्तमान मामले में अनुच्छेद (iii) में पर्याप्त सार है, और तदनुसार मैं मानता हूँ कि निर्णय में विधि की त्रुटि है, याचिका सफल होती है और निर्णय को रद्द किया जाना चाहिए।

20. कारणों की आवश्यकता का औचित्य यह है कि कारण यह सुनिश्चित करते हैं कि मध्यस्थ ने मनमानी नहीं की है। कारण उन आधारों को प्रकट करते हैं जिन पर मध्यस्थ उस निष्कर्ष पर पहुंचा है जो किसी पक्ष के हितों को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करता है। करारत्मक रूप से कारणों का प्रावधान उचित और पर्याप्त कारणों को दर्शाता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

कारण शब्द का शाब्दिक अर्थ किसी विश्वास या कार्यप्रणाली का आधार या प्रेरणा होता है। इसी अर्थ में अधिनिर्णय में दी गई राशि के कारणों का उल्लेख होना आवश्यक है।

21. **भारत संघ बनाम मोहन लाल कपूर और अन्य**[3] के मामले में यह माना गया है कि 'कारण उन सामग्रियों के बीच की कड़ी हैं जिन पर कुछ निष्कर्ष आधारित होते हैं और वास्तविक निष्कर्ष। वे यह प्रकट करते हैं कि किसी निर्णय के लिए विषय वस्तु पर किस प्रकार विचार किया जाता है, चाहे वह विशुद्ध रूप से प्रशासनिक या अर्ध-न्यायिक, हो या नहीं। । इनमें विचारे गए तथ्यों और निकाले

[3] (1973) 2 एससीसी 836

गए निष्कर्षों के बीच तर्काधार संबंध स्पष्ट होना चाहिए। केवल इसी तरह से दर्ज की गई राय या निर्णय को स्पष्ट रूप से न्यायसंगत और उचित सिद्ध किया जा सकता है। अतः, जहाँ मध्यस्थ ने किसी विशेष मद पर किसी विशेष राशि को प्रदान करने के अपने आधार को स्पष्ट नहीं किया है, जैसा कि वर्तमान मामले में है, तो किसी भी तर्क के आधार पर इसे तर्कसंगत अधिनिर्णय नहीं माना जा सकता। केवल सामान्य शब्दों में यह संतुष्टि दर्ज करना कि दावाकर्ता को नुकसान हुआ होगा और उसके बाद बिना किसी आधार को बताए अधिनिर्णय का एक निश्चित प्रतिशत प्रदान करना, राशि प्रदान करने का तर्कसंगत आधार नहीं माना जा सकता।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

22. वर्तमान मामले में, 1996 के अधिनियम की धारा 31(3) के तहत वैधानिक प्रावधानों के अतिरिक्त, मध्यस्थ की नियुक्ति के आदेश में मध्यस्थ के लिए युक्तियुक्त अधिकारिता पारित करना भी आज्ञापक किया गया था। हालांकि, चूंकि इस न्यायालय ने पाया है कि निर्णय कई बिंदुओं पर युक्तियुक्त नहीं है, इसलिए इसे इस आधार पर भी रद्द किया जाना आवश्यक है।

23. **रामसहाय शेदुरम बनाम हरिश्चंद्र दुलचंदजी और अन्य**[4] के मामले में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के निर्णय के आधार पर, प्रतिवादी/दावाकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने तर्क दिया कि अपीलार्थी द्वारा दायर

[4] एआईआर 1963 एमपी 143

प्रतिदावे को भी स्वीकार कर लिया गया है और उसे अंतिम दावे की राशि में समायोजित कर दिया गया है, और अपीलार्थी अपने पक्ष में दिए गए निर्णय को चुनौती देने की स्थिति में नहीं है, इसलिए वह प्रतिवादी/दावाकर्ता के पक्ष में दिए गए निर्णय के अन्य भाग को भी चुनौती देने का हकदार नहीं है, अतः यह अपील इस आधार पर खारिज कर दी जानी चाहिए। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के उक्त निर्णय में, अनुच्छेद-17 में निम्नलिखित निर्णय लिया गया है:-

> 17. इसी दौरान, हमें मामले का एक ऐसा पहलू मिला जिस पर अधीनस्त न्यायालय ने उचित ध्यान नहीं दिया है। अप्रैल में किसी समय, मध्यस्थ द्वारा एक निर्णय दिया गया था। लगभग 6000/- रुपये से संबंधित विवाद का एक छोटा हिस्सा निपटाया गया। मई के अंत में, साइटों से एकत्रित सामग्री के संबंध में एक और विवाद उत्पन्न हुआ। हालांकि यह स्पष्ट नहीं है कि 600/- रुपये से संबंधित विवाद पर निर्णय इस निर्णय में शामिल किया गया है या नहीं, यह स्पष्ट है कि भवन निर्माण सामग्री से संबंधित निर्णय निर्णय में शामिल नहीं किया गया है (और किया भी नहीं जा सकता था), और इसे अलग से दिया गया था। दोनों पक्षों ने उस निर्णय को स्वीकार कर लिया है और तदनुसार उन्हें आवंटित सामग्री का उपयोग कर लिया है। अब, माध्यस्थम में किसी पक्ष के लिए, जिसने मध्यस्थ के निर्णय के एक हिस्से को स्वीकार कर लिया है और उससे

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

लाभान्वित हुआ है, शेष हिस्से पर सवाल उठाना संभव नहीं है। इस मध्यस्थ को इन भवन निर्माण अनुबंधों से उत्पन्न होने वाले पक्षों के बीच के सभी विवादों का निर्णय करना था। सुविधा के लिए, उन्होंने निर्णय में उन विवादों का निर्णय दिया जिनकी गणना धन के संदर्भ में की जा सकती थी, जबकि उन्होंने मई के अंत में सामग्री से संबंधित विवाद का निर्णय अलग से किया। पूरी प्रक्रिया वास्तव में एक ही माध्यस्थम है जिसमें निर्णय की आंशिक स्वीकृति या चुनौती की अनुमति नहीं दी जा सकती। इस विषय पर वैधानिक मिसालें मौजूद हैं; लेकिन सिद्धांत बहुत सरल है। माध्यस्थम में शामिल पक्ष को मध्यस्थ के निर्णय को समग्र रूप से स्वीकार करना चाहिए और अपने लिए उपयुक्त भाग का लाभ उठाने के बाद, उस भाग को चुनौती देने का अधिकार नहीं है जो उसे उपयुक्त न लगे। इस दृष्टिकोण से, अपीलार्थी को किसी भी आधार पर निर्णय पर आपत्ति करने से रोका जाना चाहिए था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

ऐसा प्रतीत होता है कि मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के समक्ष दिया गया निर्णय एक अलग आदेश द्वारा पारित किया गया था और आदेश के एक भाग का पक्षों द्वारा अनुपालन किया गया था जबकि दूसरे भाग को चुनौती दी गई थी। इस स्थिति में, यह माना गया है कि माध्यस्थम में शामिल कोई पक्ष, जिसने अपने लिए उपयुक्त

भाग का लाभ उठा लिया है, उस भाग को चुनौती नहीं दे सकता जो उसे उपयुक्त नहीं लगता।

24. वर्तमान मामले में, अधिनिर्णय समग्र है। संपूर्ण अधिनिर्णय को जिला न्यायाधीश के समक्ष चुनौती दी गई थी और जिला न्यायाधीश का वह आदेश जिसमें अधिनिर्णय को शामिल किया गया है, इस न्यायालय के समक्ष चुनौती के अधीन है। मात्र इस आधार पर कि प्रतिदावा उठाया गया है और उसे कुछ हद तक स्वीकार भी कर लिया गया है, जबकि अंतिम निर्णय में अपीलार्थी को 1,73,22,869.95 रुपये की भारी राशि का भुगतान करना पड़ा, संपूर्ण अधिनिर्णय को चुनौती देना, अलग से पारित अधिनिर्णय को चुनौती देने से बिल्कुल अलग है, जिसमें से एक पर कार्रवाई की गई थी, जैसा कि मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के समक्ष **रामसहाय शेदुरम** (पूर्वोक्त) मामले में हुआ था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

25. इस न्यायालय की राय में, चूंकि संपूर्ण निर्णय जिला न्यायाधीश के समक्ष चुनौती के अधीन था, इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि अपीलार्थी ने निर्णय के उस भाग को स्वीकार कर लिया है या उसका पालन किया है जो उसके लिए उपयुक्त था। वास्तव में, चूंकि दी गई राशि की गणना समग्र रूप से की गई है, इसलिए निर्णय को चुनौती विधि के दायरे में ही दी जानी चाहिए और अपीलार्थी को संपूर्ण निर्णय को चुनौती देने से नहीं रोका जा सकता। यदि इसे स्वीकार कर लिया जाता है, तो ऐसे सभी मामलों में जहां प्रतिदावा उठाया जाता है, प्रतिदावे के

मद में मामूली राशि का निर्णय दिया जा सकता है जबकि दावाकर्ता द्वारा उठाई गई बड़ी राशि को स्वीकार कर लिया जाएगा और पीड़ित पक्ष द्वारा दायर अपील को सुनवाई योग्य न मानते हुए अपास्त कर दिया जाएगा। यदि पीड़ित पक्ष को बिना तर्क के दिए गए निर्णय के आधार पर बड़ी राशि का भुगतान करने के लिए कहा जाता है, तो उसे 1996 के अधिनियम के तहत अपील दायर करने के अधिकार से इस आधार पर वंचित नहीं किया जा सकता।

26. पूर्वोक्त के मद्देनजर, चूंकि इस न्यायालय ने पाया है कि मध्यस्थ अधिकरण को माध्यस्थम की कार्यवाही करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है क्योंकि नियुक्ति स्वयं करार की शर्तों के विपरीत थी और यह **नगर निगम, जबलपुर और अन्य** (पूर्वोक्त) के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय से स्पष्ट रूप से पूरी तरह सुसंगत होती है और इस आधार पर भी कि निर्णय तर्कसंगत नहीं है, अपीलार्थी द्वारा उठाए गए अन्य आधारों पर विचार करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

27. तदनुसार, अपील स्वीकार की जाती है और आक्षेपित अधिनिर्णय को अपास्त किया जाता है।

सही /-

आई. एम. कुद्दूसी

न्यायमूर्ति

सही /-

प्रशांत कुमार मिश्रा

न्यायमूर्ति

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

Translated by:- Gajendra Prakash Sahu